सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट)
SUCI (C) का मुखपत्र

वर्ष-37 अंक 11 | 7 जून से 21 जून 2022 | मुख्य संपादकः कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य : 2 रुपये (पाक्षिक)

भाजपा-संघ परिवार फिर से भड़का रहा है मंदिर-मस्जिद विवाद

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 24 मई को एक बयान जारी कर कहा :

"जब देश के आम लोग अभूतपूर्व रूप से बढ़ती महंगाई, छंटनी, बेरोजगारी, गरीबी, हर स्तर पर बेलगाम भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं से अत्यंत पीड़ित हैं, ऐसे में भाजपा-संघ परिवार जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, साम्प्रदायिक आधार पर लोगों को बांटने तथा साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए, वैज्ञानिक मानसिकता को नष्ट करते हुए मध्यकालीन धार्मिक कट्टरता को प्रोत्साहित करने और खास तौर पर अपने 'हिंदू वोट बैंक' को मजबूत करने के लिए फिर से मंदिर-मस्जिद विवाद को भड़का रहा है।

यह आम लोगों के हितों पर खतरनाक हमला है। हम भाजपा-संघ परिवार के इस फासीवादी अनर्थकारी मंसूबे की निंदा करते हैं।

हम तमाम जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी मानसिकता वाले लोगों का आह्वान करते हैं कि वे देश के इस संकट की घड़ी में आगे आयें और इस खतरनाक हमले को परास्त करने के लिए एकताबद्ध दीर्घस्थाई आंदोलन गठित करें।"

नफरत की राजनीति के तमाशबीन क्यों बने हुए हैं प्रधानमंत्री?
100 पूर्व नौकरशाहों ने लिखा सख्त पत्र

देश के 100 सेवानिवृत्त नौकरशाहों (आईएएस, आईएफएस व आईआरएस) ने शासक पार्टी भाजपा और संघ परिवार की ओर से देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह से नफरत और असहिष्णुता का माहौल पैदा करने की साजिश रची जा रही है, उस पर गहरी चिंता जताते हुए और प्रधानमंत्री को अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने की अपील करते हुए हाल ही में एक पत्र भेजा है।

इस पत्र में उन्होंने दिल्ली, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में अशांति पैदा करने की हालिया घटनाओं के बारे में लिखा है कि जो कुछ घट रहा है, वह भारत के संविधान की मूल भावना और कानून के शासन के खिलाफ है। देश में बहुसंख्यक समुदाय का दबदबा जबरदस्त तरीके से कायम होता जा रहा है। गौरतलब है कि इनमें हर एक प्रदेश में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भी पुलिस मोदी सरकार के अधीन है। उन्होंने सरकार की ओर से तत्काल आवश्यक कदम उठाने की मांग की है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खान-पान की अपनी आदतों, पहनावे, रीति-रिवाजों और संस्कृति को कायम रख सकें। नरेन्द्र मोदी के शासन में देश के दबे-पिसों, गरीबों और हाशिये के लोगों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर सुनियोजित ढंग से उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, पत्र में इस बात का जिक्र करते हुए इन नौकरशाहों ने इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने की मांग की है। उनका कहना है कि पार्टी के आला कमान की राजनैतिक स्वीकृति से ही ऐसी घटनाएं घट रही हैं। उसकी मर्जी के बिना ऐसी घटनाएं घटना संभव नहीं हैं। उनका आरोप है कि हाल ही में दिल्ली में

(शेष पृष्ठ 7 पर)

मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष विचार ही शोषण से मुक्ति का एकमात्र रास्ता

24 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस सभा में कॉमरेड प्रभास घोष का भाषण

(24 अप्रैल को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के 75 वें स्थापना दिवस पर कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी द्वारा आयोजित विशाल जनसभा में पार्टी के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने अपने विचार व्यक्त किये। हम यहां उनके भाषण का हिन्दी रूपांतर प्रस्तुत कर रहे हैं।)

कॉमरेड अध्यक्ष, कॉमरेड्स और मित्रो,

आप लोग सभी यह समझ रहे हैं कि कितनी असहनीय परिस्थिति के बीच हमें अपनी पार्टी के 75 वें स्थापना दिवस का आयोजन करना पड़ रहा है। इस सभा में आपके समक्ष दो प्रस्ताव पेश किये गये हैं। उनमें भी आपने सुना है कि अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या प्रदेशों के हर मामले में हर तरफ से एक भयंकर आक्रमण का हम सामना कर रहे हैं। इस संकटपूर्ण स्थिति में हमारे महान शिक्षक एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी के संस्थापक महासचिव महान मार्क्सवादी चिंतक कॉमरेड शिवदास घोष की सीखों के आधार पर हम इन समस्याओं को किस प्रकार समझ सकते हैं और अपने कर्तव्य का निर्धारण कर सकते हैं, इसके बारे में मेरी जो समझदारी है, उसके अनुसार मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखूंगा।

अगर रूस में समाजवाद होता, तो नहीं होते यूक्रेन पर ऐसे हमले

आप सभी यह जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से साम्राज्यवादी रूस ने यूक्रेन जैसे एक छोटे देश पर आकाश मार्ग, जलमार्ग और स्थल मार्ग से घेरकर आक्रमण कर रहा है और उस देश को एक मलबे के ढेर में तब्दील कर रहा है। रूस का यह कौन सा रूप है! आप लोगों को मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा कि जब दूसरे विश्वयुद्ध की आग जल रही थी, जब फासीवादी जर्मनी,

इटली और जापानी साम्राज्यवाद सम्मिलित रूप से हमले कर रहे थे, पूरा यूरोप लगभग उनके कब्जे में था, फ्रांस भी जर्मन सेना के कब्जे में आ चुका था, इंग्लैंड लगभग हार के कगार पर पहुंच चुका है, उस वक्त मनीषी रोमा रोलां, बर्नार्ड शॉ, आइंस्टाइन सहित यूरोप के नामी-गिरामी मनीषी और हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के योद्धा—सभी सहमे हुए थे। इस मानव सभ्यता की रक्षा कौन करेगा? गुरुदेव रवीन्द्रनाथ मृत्यु शैया पर थे। वे हर दिन युद्ध का समाचार लेते थे। प्रशांत चन्द्र महालनविस ने लिखा है कि जब रवीन्द्रनाथ ने सुना कि फासीवादी जर्मनी आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें दुख हुआ। अखबार को उन्होंने दूर फेंक दिया। अंतिम ऑपरेशन के दिन जब उन्होंने सुना कि महान स्तालिन के नेतृत्व में लाल सेना ने जर्मनी की प्रगति को कुछ हद तक रोक दिया है, तो वे खुशी से झूम उठे और बोले कि यही लोग सकेंगे, यही लोग कर सकेंगे। पूरे विश्व के मनीषी, स्वतंत्रता सेनानी, फासीवाद विरोधी ताकतें—सभी उस वक्त सोवियत रूस की ओर देख रहे थे। महान स्तालिन इस युद्ध का संचालन कर रहे थे और दिन-रात मेहनत कर रहे थे। मार्शल जुकॉव ने लिखा है कि उस वृद्ध अवस्था में भी कब स्तालिन आराम करते थे, कब सोते थे, हमें पता भी नहीं चलता था। जब-तब वे हमें बुला लेते थे और युद्ध की योजनाओं पर चर्चा होती थी। जर्मनी के हाथों स्तालिन का एक बेटा बंदी था। जर्मनी ने यह प्रस्ताव रखा था कि सोवियत यूनियन के पास बंदी जर्मन सेना के एक मार्शल को छोड़ने पर वे स्तालिन के बेटे को छोड़ देंगे। स्तालिन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि एक आम लेफ्टिनेंट के बदले किसी मार्शल का आदान-प्रदान नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि उस पर शायद बहुत अत्याचार होगा, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि वह अपने पितृभूमि से विश्वासघात नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि क्या भयंकर है यह युद्ध। कितने माता-पिता अपनी औलादों को खो रहे हैं। उन्हीं स्तालिन ने दूसरे विश्वयुद्ध में फासीवादी ताकतों को परास्त कर पूरी दुनिया की रक्षा की थी।

यूक्रेन पर अपना आधिपत्य कायम करने के लिए ही साम्राज्यवादी रूस और अमेरिकी साम्राज्यवाद के बीच चल रही है प्रतिद्वंद्विता

स्तालिन की मृत्यु के पश्चात जब साम्राज्यवादियों की चालाकी के कारण और सोवियत यूनियन के अंदर प्रति क्रांतिकारी षड्यंत्र और साम्राज्यवाद के एजेंट खुश्चेव की साजिश से सोवियत यूनियन में समाजवाद का पतन हुआ, पूंजीवाद पुनर्स्थापित हुआ, तब साम्राज्यवादी दुनिया के शिरोमणि पूंजीपति लोग और हमारे देश के बुर्जुआ अखबार—सभी ने हर्षोल्लास के साथ कहा कि रूस में सोवियत समाजवाद का पतन हो चुका है और लोकतंत्र की स्थापना हुई है। कौन-सा लोकतंत्र? आज के पुतिन के रूस की ओर नजर उठाकर देखिए। समाजवाद खत्म कर पूंजीवाद की स्थापना करने के बाद आज रूस

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सभी पूंजीवादी–साम्राज्यवादी देश लोकतंत्र को ध्वस्त कर अपना रहे हैं फासीवादी चरित्र

कॉमरेड प्रभास घोष का भाषण...

(पृष्ठ 1 का शेष)

एक साम्राज्यवादी देश में तब्दील हो चुका है और एक छोटे-से देश पर स्पेशल मिलिट्री एक्शन के नाम पर भयंकर हमला चला रहा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद ने एक समय सोवियत समाजवाद को बर्बाद करने के लिए मिलिट्री गुट नाटो बनाया था। आज भी यूरोप में अमेरिकी मिलिट्री, आर्थिक और राजनीतिक दबदबा कायम रखने के लिए उसी मिलिट्री गुट को उसने बरकरार रखा है। इसमें वह यूक्रेन को शामिल करना चाहता है। साम्राज्यवादी रूस के डर से सहमा हुआ यूक्रेन भी वही चाहता है। आज के इस सभा के प्रस्ताव में भी हमने नाटो के खिलाफ कहा है। हम यह मांग करते हैं कि मिलिट्री समझौते रद्द किये जायें। फिर यूक्रेन नाटो के साथ जुड़ रहा है। इस बहाने साम्राज्यवादी रूस का यूक्रेन पर हमला भी सही नहीं है। कल अगर बांग्लादेश सरकार साम्राज्यवादी चीन के साथ सैन्य समझौता कर सैन्य अड्डा बनाये, तो क्या भारत पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश पर हमला कर देगा? अगर भारत अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ समझौता कर भारत में अमरीकी साम्राज्यवाद का सैन्य अड्डा बनाता है, तो क्या इस आधार पर पड़ोसी चीन भारत पर हमला कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। यह बहाना हमला करने का ही एक बहाना है। दो साम्राज्यवादी ताकतों के बीच द्वन्द्व–यूक्रेन को कौन अपने वश में करेगा? यूक्रेन की खनिज सम्पदा, कृषि सम्पदा, बंदरगाह, समुद्र मार्ग–हर चीज पर कब्जा करने के लिए आज रूसी साम्राज्यवाद यह हमला चला रहा है। फिर चूंकि यूक्रेन हाथ से निकल रहा है, इसलिए अमेरिकी साम्राज्यवाद इसका विरोध कर रहा है। रूस का यूक्रेन पर हमले के पीछे एक और मकसद है, वह है यूक्रेन के अंदर से रूस यूरोप में गैस आपूर्ति करना चाहता है। फलस्वरूप साम्राज्यवादी लूट का मकसद भी इसमें शामिल है। एक और बात है –मौजूदा पूंजीवादी रूस में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है। मजदूर वर्ग शोषित और उत्पीड़ित है। इसके खिलाफ जनता में जबरदस्त विक्षोभ है। रूस में फिर लोग जाग रहे हैं। 80% लोगों की राय है कि समाजवाद फिर से आना चाहिए। फिर से महान लेनिन, स्तालिन की तस्वीरों को लेकर हजारों लोग संगठित हो रहे हैं। इसलिए रूस के साम्राज्यवादी शासक वर्ग में डर पैदा हो गया है। वह रूस की जनता का ध्यान दूसरी ओर भटकाना चाहता है और इसीलिए उसे इस युद्ध की जरूरत है। फिर अमेरिकी साम्राज्यवाद को भी इस युद्ध की जरूरत है। उनके देश में भी जबरदस्त विक्षोभ-प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ सालों पहले अक्यूपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन हुआ था। यूरोप में भी मजदूर हड़ताल की बाढ़-सी आ गयी है। पूरी दुनिया के लोगों का विक्षोभ फूट रहा है। स्वत:स्फूर्त आंदोलन में लोग शामिल हो रहे हैं। इससे लोगों का ध्यान को भटकाने के लिए इस युद्ध को इस्तेमाल करना ही साम्राज्यवादियों के लिए जरूरी हो गया है।

बहुत पहले ही महान स्तालिन ने यह दिखाया कि साम्राज्यवादी-पूंजीवादी लोग इस संकट से राहत पाने के लिए देश को मिलिटराइजेशन ऑफ इकोनॉमी की ओर ले जा रहे हैं। यानी हथियार बनाने और उसके व्यापार पर ही अर्थव्यवस्था निर्भरशील हो गयी है। पूंजीवाद के शोषण से जर्जर लोगों के पास रोजाना इस्तेमाल की चीजें खरीदने की ताकत नहीं है। रोजाना इस्तेमाल की चीजों का बाजार आज संकुचित हो गया है। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण किया जा रहा है। यानी हथियार उत्पादन करो, राज्य उन हथियारों को जनता के पैसे से खरीदेगा। और हथियारों के इसी उद्योग के लिए उन्हें बाजार चाहिए। यदि बनाये गये हथियारों का इस्तेमाल न हो, तो नये हथियार बनाना संभव नहीं होगा। इसलिए युद्ध की आवश्यकता है। इसलिए यूक्रेन को मदद करने के नाम पर अमेरिका उसे हथियार दे रहा है। यूरोप के साम्राज्यवादी देश भी अपने हथियारों के उद्योग को तरोताजा करने के लिए इस युद्ध का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिकी साम्राज्यवाद यूरोप में अपने आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य ताकत में बढ़ोतरी कर रहा है। रूस के पूंजीपतियों के हाथों में जो विदेशी बाजार है, उस पर भी वह कब्जा करना चाहता है।

दूसरी ओर इस मामले में भारत की भूमिका के बारे में भी आप जानते हैं। भारत के पूंजीवादी शासक रूस के इस हमले का विरोध नहीं कर रहे हैं। यहां पर भारत के पूंजीपतियों का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। भारत चाहता है कि उसे रूस से सस्ते दरों पर तेल और हथियार मिले। इसके अलावा रूस और चीन के बीच जो एकता है, उसके लिए चीन और भारत की सीमा को लेकर रूस सीधे तौर पर चीन के पक्ष में न चला जाये, इसके लिए भारत सरकार भी रूस के इस हमले के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है। साम्राज्यवादी हमले से एक देश पूरी तरह से तबाह हो रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, गांव शहर-तबाह किये जा रहे हैं, लेकिन भारत इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। बल्कि वह परोक्ष रूप से इसका समर्थन ही कर रहा है। इराक मौत के हथियार तैयार कर रहा है, यह बहाना बनाकर अमरीकी साम्राज्यवाद ने जब इराक पर हमला किया था, इराक को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, उस वक्त भी भारत के पूंजीवादी शासकों ने अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध नहीं किया था। उस वक्त भी उन्होंने वैसा ही रवैया अपनाया था। यह बात भी हमें याद रखनी चाहिए।

सभी पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देश लोकतंत्र को ध्वस्त कर अपना रहे हैं फासीवादी चरित्र

साम्राज्यवादियों का कहना है कि यूक्रेन में यह जो लड़ाई हो रही है, यह लोकतंत्र और तानाशाही के बीच लड़ाई है। जैसे अमेरिकी साम्राज्यवाद, यूरोपीय साम्राज्यवाद–यह सब लोकतंत्र के रक्षक हैं और रूस में तानाशाही शासन है। महान लेनिन की सीख से हमने यह भली-भांति जाना है। बहुत पहले ही उन्होंने यह कह दिया था कि पूंजीवाद अपने प्राथमिक काल में लोकतंत्र और व्यक्ति स्वतंत्रता पर जितना महत्व दिया करता था, साम्राज्यवादी स्तर पर पहुंचकर वही पूंजीवाद आज लोकतंत्र को तबाह कर रहा है और व्यक्ति स्वतंत्रता को खत्म कर रहा है। वह सेना और नौकरशाही पर निर्भरशील होता जा रहा है। महान स्तालिन ने कहा है कि बुर्जुआ लोकतंत्र और स्वतंत्रता के प्रश्न को पूंजीवाद ने अपने पैरों तले रौंद दिया है और मिट्टी में मिला दिया है। आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि एसयूसीआई(सी) की स्थापना के एक वर्ष बाद ही 1949 में महान शिवदास घोष ने कहा था कि विश्व के किसी भी पूंजीवादी देश में आज लोकतंत्र नाममात्र भी नहीं है। विकसित या पिछड़े–सभी साम्राज्यवादी-पूंजीवादी देशों में आज मानव सभ्यता को बर्बाद करनेवाला फासीवाद कायम हो चुका है। पूंजीवाद ने ही फासीवाद को कायम किया है। उन्होंने कहा था कि पूंजी एकाधिकारी स्तर पर पहुंचकर मुट्ठीभर ध नकुबेरों के हाथों में इकट्ठा हो चुकी है। राजनीतिक क्षेत्र में न्यायपालिका यानी न्याय विभाग और लेजिसलेटिव यानी संसद और विधानसभा की के अधिकारों को घटाकर नौकरशाह के हाथों सारे अधिकार केन्द्रित हो रहे हैं। चिंतन के क्षेत्र में एक ओर अध्यात्मवाद, धार्मिक उन्माद, उग्र राष्ट्रवाद और परम्परावाद की लगातार चर्चा हो रही है, पूंजीवाद अपने प्राथमिक युग की लोकतांत्रिक चेतना सेक्यूलर मानवतावाद को त्याग चुका है। दूसरी ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पूरी तरह तबाह कर केवल कुछ टेक्निकल काम के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है और विज्ञान के तकनीकी पक्ष को ही प्रोत्साहित किया जा रहा है। तरह तरह से विभिन्न देशों में इस प्रकार से फासीवाद का निर्माण हो रहा है। जो पार्टी सत्तासीन हो रही है, वह पूंजीवाद के हित में इस फासीवाद को ही ताकतवर बना रही है। भारत में कांग्रेस के शासन में इसकी शुरुआत हुई थी। आज बीजेपी उसे और ज्यादा मजबूत कर रही है। फलस्वरूप लोकतंत्र का कहीं कुछ भी बचा नहीं है।

हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का जो नारा लगाया गया था, वह आज एक मजाक बन चुका है। पूरी दुनिया में जबरदस्त आर्थिक विषमता कायम है। 1% एकाधिकारी पूंजीपति मल्टीनेशनलों के पास पूरी दुनिया की 70% से 75% सम्पदा है। बाकी 99% लोग बिल्कुल कंगाल और पूरी तरह सर्वहारा बन चुके हैं। हमारे देश की हालत भी कुछ ऐसी ही है। यहां भी भाजपा के शासन में 1% पूंजीपति 324.5 लाख करोड़ रुपये की सम्पदा के मालिक हैं। बाकी 83 करोड़ भारतीयों की रोजाना आमदनी 20 रुपये मात्र है। 20 करोड़ लोग हर दिन भूखे रहते हैं। कहां है समानता? कहां है भाईचारा? पूरी दुनिया में बार-बार दूसरे देशों पर हमले, साम्राज्यवादी युद्ध, धार्मिक मुद्दों पर और राष्ट्रीयता के नाम पर झड़पें, मारामारी–यही है पूंजीवाद का भाईचारा। स्वतंत्रता भी सिर्फ एकाधिकार पूंजीपतियों के लिए ही है। साम्राज्यवादियों की खुली लूट के लिए है सम्पूर्ण स्वतंत्रता। दूसरी ओर करोड़ों शोषित लोग पूंजीवाद की गुलामी की जंजीरों में कैद हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता, विरोध, आंदोलन वगैरह को हर जगह निर्ममता से कुचला जा रहा है। 'बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल' किताबों में है, मगर वास्तव में वह आज बन गया है 'बाई द मनी पावर, फॉर द मनी पावर, ऑफ द मनी पावर'। किसका मनी पावर? इन साम्राज्यवादियों का, एकाधिकार पूंजीपतियों का, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं का। आज हर कुछ इनके द्वारा ही नियंत्रित है। मीडिया और नौकरशाह इनके द्वारा संचालित हैं। वे अनगिनत गुंडों को पाल रहे हैं। मनी पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, क्रिमिनल और मसल पावर और मीडिया पावर–यही लोग सबकुछ संचालित करते हैं। वोट भी यही लोग तय करते हैं।

जनता को भिखारी बनाकर बुर्जुआ पार्टियों ने उनके मर्यादाबोध को भी कर दिया है नष्ट

आज दुनिया के सभी देशों में इलेक्शन इज अ बिग डिसेप्शन। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैस टर्न्ड इनटू वर्सट फॉर्म ऑफ अ फासिस्ट ऑटोक्रेसी। (यानी चुनाव एक बड़ा धोखा है। संसदीय लोकतंत्र आज जघन्य फासीवादी तानाशाही में तब्दील हो चुका है।) यह स्थिति दुनिया में हर जगह है। हमारे देश में भी वोट के जरिये क्या होता है, वह आप जानते हैं। हमारे देश में अभी चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, आरजेडी हो, अकाली दल हो, डीएमके हो, एडीएमके हो, तृणमूल कांग्रेस हो, वोट के कुछ दिनों पहले से ही वे निवेश करने लगते हैं। करोड़ों लोग भूखे हैं। उनके पास रोजगार नहीं है, खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, इज्जत-आबरू संभालने के लिए कपड़े नहीं हैं। रोज सैकड़ों लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हजारों लोग भूखे दिन गुजार रहे हैं। ऐसी एक हालत कायम है। इन भूखे लोगों को वे 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूं भीख में देते हैं। इसके साथ आयुष्मान भारत, लक्ष्मी भंडार कन्याश्री आदि विभिन्न तरह के श्री–इन चीजों के जरिये वे वोट से पहले निवेश करते हैं। सभी राज्य सरकारें, इस राज्य की तृणमूल सरकार तथा केन्द्र की भाजपा सरकार ने यही रास्ता अपनाया है। भूखे लोग को एक मुट्ठी अनाज मिल जाये, तो वे कुछ हद तक खुश होते हैं। वे पढ़े लिखे नहीं हैं और सचेत भी नहीं है। अचेत, अनपढ़, असंगठित, राजनीतिक चेतना रहित लोग आज पूरी तरह असहाय हैं। वे नहीं जानते हैं कि सरकार से दया की भीख नहीं, बल्कि सरकार से नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवा, रोटी, कपड़ा और मकान पाना उनका जायज हक है। यह उन्हें नहीं पता कि सरकार उन्हीं के पैसों से चलती है। इसलिए वह मांग नहीं उठा पाते हैं। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार उन्हें खैरात में चीजें दे रही है। पूरे देश की जनता को भाजपा, तृणमूल, कांग्रेस और बाकी लोग इसी प्रकार भिखारी बना रहे है। वे उन्हें सोच और चेतना तथा मान-सम्मान से महरूम भीक्षावृत्ति की मानसिकता वाले लोगों में तब्दील कर रहे हैं। यह भी एक बड़ा खतरा है। एक बात अब प्रचलित हो गयी है। थोड़ा कुछ मिलने पर लोग कह रहे हैं कि फिर भी कुछ तो दे रहे हैं, कुछ तो हमें मिल रहा है। यह सब चुनाव से पहले हो रहा है। और सभी जानते हैं कि

(शेष पृष्ठ 4 पर)

आइए, विश्व पूंजीवाद–साम्राज्यवाद के खिलाफ मिलकर लड़ें

18वीं डब्ल्यूएफटीयू कांग्रेस के प्रतिनिधियों से एआईयूटीयूसी की जोरदार अपील

रोम : 6-8 मई, 2022

प्रतिनिधि साथियो,

ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) की अखिल भारतीय कमेटी, इटली के ऐतिहासिक शहर रोम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आयोजित वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (डब्ल्यूएफटीयू) की 18वीं कांग्रेस के सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। विश्व पूंजीवाद-साम्राज्यवाद के हालात और विश्व सर्वहारा वर्ग और अन्य शोषित जनता के आगे के कार्यभारों का जायजा लेने के लिए दुनिया भर से यहां एकत्रित हुए सभी योद्धाओं को लाल सलाम।

2016 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित डब्ल्यूएफटीयू की 17वीं कांग्रेस के बाद से बहुत कुछ हो चुका है। विश्व सर्वहारा वर्ग कई घटनाओं का गवाह है, जिन्होंने तब से उनके जीवन और आजीविका को प्रभावित किया है। भयानक कोविड-19 महामारी के बारे में क्या कहें, जिसने अभूतपूर्व मृत्यु, पीड़ा, लॉकडाउन, सामान्य जीवन की अव्यवस्था, देश के भीतर या एक देश से दूसरे देश में श्रमिकों का प्रवास, रोजगारहानि, आय में कमी आदि का कहर कम से कम 2 साल से अधिक की अवधि तक बरपाया, जो अभी भी जारी है। दुनिया के लगभग सभी देशों ने सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाया, जिसके चलते छोटे-बड़े उद्योग, व्यापार-वाणिज्य, यहां तक कि परिवहन, ट्रेनें, बसें, शैक्षणिक संस्थान, होटल और रेस्तरां, सिनेमा हॉल आदि सबकुछ ठप हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया ठहर-सी गयी हो।

आइए, इस महामारी से पूरी दुनिया को हुई तबाही पर एक नजर डालते हैं। अप्रैल 2022 के अंतिम सप्ताह तक, कोविड संक्रमितों की संख्या 51 करोड़ से अधिक थी, जबकि मृतकों की संख्या 60 लाख से अधिक थी। भारत में आधिकारिक मौत का आंकड़ा 5 लाख से अधिक था, जबकि अनौपचारिक डब्ल्यूएचओ का दावा 40 लाख से अधिक था, जो कम से कम 8 गुना है! वास्तव में एक रूह कंपा देनेवाला तथ्य है। कोविड-19 ने पूरी तरह से उजागर कर दिया है कि सभी पूंजीवादी देशों में– चाहे वे अपेक्षाकृत उन्नत हों या पिछड़े, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जर्जर स्थिति में है। इसने साबित कर दिया है कि पूंजीवाद केवल कुछ धनकुबेरों के लाभ को अधिकतम करने के लिए है। इसे लोगों के स्वास्थ्य तथा जीवन से कोई सरोकार नहीं है।

दुनिया में कोविड महामारी के आने से पहले ही, विश्व आर्थिक परिदृश्य ढलान की ओर था। पूर्वी यूरोपीय समाजवादी देशों में तथा अंततः समाजवाद के गढ़ यानी स्वयं यूएसएसआर में प्रतिक्रांति और पूंजीवाद की बहाली के चलते साम्राज्यवादियों ने वैश्वीकरण-उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों के साथ पदार्पण किया, इस घोषणा के साथ कि अब कम्युनिस्टों और समाजवाद का खात्मा हो गया है। एकध्रुवीय दुनिया खुशहाल होने जा रही है, क्योंकि यह बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित है और युद्धों का युग समाप्त हो गया है! लेकिन क्या देखा जा रहा है? दुनिया के करोड़ों मेहनतकशों की खुशहाली की क्या बात करें, उनका अस्तित्व पशु-समान हो गया है। सभी देशों के एकाधिकारी पूंजीपति अकूत मुनाफा बटोर रहे हैं। उनकी सम्पत्ति का आंकड़ा आकाश छू रहा है। विश्व में, विशेष रूप से 2009 के बाद से जबरदस्त मंदी देखी गयी और विश्व पूंजीवाद के गढ़, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर में जन आंदोलनों की बाढ़ आ गयी।

विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कभी भी इससे उबर नहीं सकी। बहुत पहले महान स्तालिन ने दिखाया था कि द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले विश्व पूंजीवाद की जो भी सापेक्ष स्थिरता थी, वह अब नहीं रही। यह एक संकट से निकल रहा है, दूसरे एक बड़े संकट में डूब जाने के लिए। ऐसी एक पृष्ठभूमि में ही कोविड-19 ने दुनिया को आक्रान्त किया। लोगों की बेबसी का फायदा उठाकर और कोविड-19 की आड़ में भारत सहित सभी पूंजीवादी देशों में शासक पूंजीपति वर्गों ने ईंधन, भोजन, दवा आदि सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि की है। आकाश छूती मंहगाई, रोजगार हानि और बढ़ती बेरोजगारी ने लाखों मेहनतकशों के जीवन को कंगाली और बदहाली में धकेल दिया है। महामारी के दो साल के बाद से मेहनतकश लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। हम भारत पर पड़े प्रभाव का हवाला दे सकते हैं, जो सभी पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति को इंगित करेगा।

भारत में 2020 के एक ही साल में 11,716 कारोबारियों ने आत्महत्याएं की (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी)। एक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 और 2022 के बीच 6000 से अधिक छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों ने उत्पादन बंद कर दिया। आईएमएफ के रिकॉर्ड के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय पड़ोसी बांग्लादेश की तुलना में कम हो गयी है। बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 2227 डॉलर है, जबकि भारत में यह 1947 डॉलर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्केल पर भारत कुल 116 देशों में से 101वें स्थान पर है और इस प्रकार यह पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं नेपाल से भी नीचे है। भारत सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में, भारत में महामारी के हमले से पहले ही बेरोजगारी 45 वर्षों में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी थी। सीएमआईई सर्वेक्षण 2021 ने इस तथ्य को उजागर किया कि 84% परिवारों की आय में गिरावट आयी है। 2020 में 4 करोड़ 60 लाख भारतीयों को घोर गरीबी में ध केल दिया गया, जो उस अवधि में वैश्विक संख्या का लगभग आधा है। 2019 की तुलना में 1 करोड़ 30 लाख से अधिक महिलाएं काम से बाहर हो गयी हैं।

पददलित मेहनतकश लोगों के लिए यह एक निराशाजनक तस्वीर है, जबकि मुट्ठीभर अमीर भारतीयों के लिए उज्जवल तस्वीर उभरती है। महामारी की अवधि के दौरान भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 143 हो गयी। अरबपतियों की कुल सम्पत्ति 300 अरब डॉलर (मार्च 2020) से बढ़कर 711 अरब डॉलर (नवम्बर 2021) हो गयी। मात्र 98 अरबपतियों की सम्पत्ति नीचे के 55.5 करोड़ यानी 40% लोगों की कुल सम्पत्ति (657 अरब डॉलर) के बराबर है। महामारी के दौर में सभी अरबपतियों की कुल सम्पत्ति दोगुनी से भी ज्यादा हो गयी। इसके अलावा, ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार, महामारी ने लिंग समानता को 99 से वापस 135 वर्ष कर दिया है।

कॉमरेडो और दोस्तो, हम आप पर तथ्यों का बोझ डालना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम उपरोक्त सभी तथ्यों को आपके सामने रखने का मौका भी नहीं गंवाना चाहते, ताकि आप खुद अनुमान लगा सकें कि किसी महामारी के अब तक के सबसे बदतरीन हमले के दौरान पूंजीवाद ने लोगों के जीवन में क्या तबाही मचाई है। यहां तक कि जब पूरी सभ्यता ठहर गयी थी, उस समय 99% आबादी के जीवन को अभूतपूर्व दुख-तकलीफ की ओर धकेलते हुए मुट्ठीभर पूंजीवादी धनकुबेरों ने अकूत सम्पत्ति बटोर ली, जबकि लाखों लोगों की तुच्छ कमाई और बचत उड़ गयी, वहीं मुट्ठीभर अमीरों ने कल्पना से परे अपनी तिजोरियों को भरा है। यहां नमूने के तौर पर पेश की गयी भारत की तस्वीर से दुनिया की तस्वीर बहुत अलग नहीं होगी।

जैसा कि कम से कम एक सदी पहले महान लेनिन ने कहा था कि अपने मरणासन्न साम्राज्यवादी चरण में यह पूंजीवाद कितना क्रूर और अमानवीय है। महामारी ने इस पूंजीवाद के अमानवीय फासीवादी चेहरे को भी खुलकर उजागर किया है। जितनी जल्दी इसे दफनाया जाये, सभ्यता के आगे बढ़ने के लिए उतना ही बेहतर है।

जब हमारी कांग्रेस हो रही है, तब हम यूक्रेन पर रूस द्वारा शुरू किये गये युद्ध में सामने आयी भयानक त्रासदी का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकते। अनमोल मानव जीवन का कितना नुकसान! इन दोनों देशों के लोगों के बीच कितना सौहार्दपूर्ण संबंध था, जो कुछ ही साल पहले तक उस महान देश यूएसएसआर का हिस्से थे, लेकिन कैसे यह क्रूर दुश्मनी में बदल गया! यह मार्क्सवाद की वैधता को ही साबित करता है, चाहे उसके दुश्मन इसके खिलाफ कितना ही हल्ला मचाते रहें। एक बार जब प्रतिक्रांति सफल हो गयी और दोनों देशों में पूंजीवाद बहाल हो गया, तो न केवल यूएसएसआर में प्रतिक्रांति हुई, बल्कि यह देश 15 स्वतंत्र देशों में भी विघटित हो गया। अपनी अत्यधिक विकसित अर्थव्यवस्था के साथ रूस एक प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में प्रकट हुआ है। पूर्वी यूरोपीय समाजवादी देशों के साथ-साथ अंततः यूएसएसआर में समाजवाद के खात्मे का लाभ उठाते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका की कप्तानी में साम्राज्यवादी शक्तियों ने इन पूंजीवादी देशों में से कई को नाटो के तहत लाने में सफलता हासिल कर ली। सभी जानते हैं कि यूक्रेन सहित कुछ देशों ने नाटो में शामिल होने का विरोध किया था, लेकिन यूक्रेन में शासन परिवर्तन के बाद इसने संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो की ओर झुकना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से इसने रूसी शासक वर्ग को नाराज कर दिया, जो यूक्रेन के विशाल बाजार के साथ-साथ अपने प्रभाव क्षेत्र को भी खोना नहीं चाहता है। यूक्रेन दो युद्धरत साम्राज्यवादी दिग्गजों, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर के लिए युद्ध का मैदान बन गया है। जबकि हम यूक्रेन पर रूस के नग्न आक्रमण की निंदा करते हैं, जिससे भारी जनहानि और नागरिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा है। साथ ही हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो शक्तियों की साजिश की भी निंदा करते हैं, जिन्होंने यूक्रेन को मोहरा बनाते हुए रूस को घेरने और कोने में धकेलने की पूरी कोशिश की है।

इस युद्ध ने एक बार फिर साम्राज्यवादियों द्वारा फैलाये गये झांसे का पर्दाफाश किया है कि समाजवादी खेमे के अंत का मतलब युद्धों का अंत भी है और महान लेनिन की महान शिक्षा की पुष्टि करता है कि साम्राज्यवाद अनिवार्य रूप से युद्धों को जन्म देता है।

यह स्पष्ट है कि पूंजीवाद जहां एक ओर अतिरिक्त पूंजी से त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर लोगों की घटती क्रय-शक्ति के चलते बाजार के अभाव से ग्रस्त है। इसलिए अतिरिक्त पूंजी निवेश करने के लिए पूंजीपति वर्ग को बाजार की आवश्यकता है। जबकि अन्य देशों को पूंजी निर्यात करना एक विकल्प है, यदि बाजार उपलब्ध हो, वहीं दूसरा विकल्प राज्य के स्वामित्ववाले उपक्रमों का निजीकरण और अंतिम उपाय के रूप में कृषि में निवेश करना है। भारत में सरकार मजदूर वर्ग के कड़े विरोध के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण पर आमादा है।

इसलिए सरकार कृषि कानून लायी, जो इजारेदार घरानों के पक्ष में और किसानों के हितों के खिलाफ थे। अब यह इतिहास है कि किसानों ने कानूनों का विरोध किया और हजारों किसानों ने जिंदादिली और बहादुरी से एक साल से अधिक समय तक राजधानी दिल्ली के सभी रास्तों को अवरुद्ध कर दिया। पुलिस की बर्बरता और 700 से अधिक लोगों की कुर्बानी के सामने, आखिरकार किसानों ने शानदार जीत हासिल की, जब सरकार ने सभी तीन किसान विरोधी कानूनों को वापस ले लिया। यह आंदोलन देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। यह मेहनतकश लोगों के अन्य वर्गों के आगे के आंदोलनों को प्रेरित कर रहा है।

अब यह विवेकशील लोगों के सामने स्पष्ट है कि पूंजीवाद-

(शेष पृष्ठ 7 पर)

यही एकमात्र पार्टी है, जिसे कभी खरीद नहीं सकते पूंजीपति

कॉमरेड प्रभास घोष का भाषण..

(पृष्ठ 2 का शेष)

चुनाव के दौरान गरीबों के मोहल्लों में, बस्तियों में, विभिन्न स्थानों पर ये पार्टियां पैसे बांटती हैं। हजारों-लाखों रुपये में वोट खरीदे जाते हैं। एक-एक वोट, 10-20 वोट, हजार-हजार रुपये में बिक जाते हैं।

ये पैसे कौन देता है? क्या ये पार्टियां देती हैं? ये पैसे देते हैं एकाधिकारी पूंजीपति लोग। ये पैसा देती हैं बहुराष्ट्रीय कम्पनियां। ये पैसे देते हैं कालाबाजारी करने वाले लोग ताकि उनका निरंकुश शोषण-लूट कायम रह सके। ये पार्टियां इनके शोषण और लूट की मैनेजर हैं। चुनाव के दौरान लाखों रुपये खर्च कर और चुनाव के बाद आम लोगों को लूट कर वे करोड़ों रुपये मुनाफा कमाते हैं। वे सभी चीजों की कीमतें बढ़ा देते हैं। क्या सरकार चाहने से महंगाई रोक नहीं सकती है? इस महंगाई के लिए केन्द्र और राज्य सरकार–दोनों ही जिम्मेदार हैं। यह सही है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस दाम पर वे खरीदते हैं, उस पर केन्द्र की भाजपा सरकार 63% और राज्य की तृणमूल सरकार 37% टैक्स लगाती है। फलस्वरूप 100% टैक्स लग जाता है। दोनों सरकारें ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके चलते लागत में वृद्धि होती है, परिवहन का खर्च बढ़ता है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों की मदद से ये सारे पूंजीपति लोग पैसे लूटते हैं। एक और कारण है कि सामानों के उत्पादन के बाद सबकुछ व्यापारियों के पास, जमाखोरों के पास, कालाबाजारियों के पास चला जाता है। बहुत दिन पहले ही कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा था कि अगर सरकार चीजों की कीमतें घटाना चाहती हैं, तो उसे राष्ट्रीय व्यापार लागू करना होगा। कल-कारखानों में जिन सामानों का उत्पादन होता हैं, कृषि क्षेत्रों में जो पैदावार होती है, सरकार उसे तय दामों पर खरीद ले और सरकार ही तय दामों पर दुकानों के जरिये उसे बेचे। ऐसा होने पर महंगाई का हमला नहीं हो पायेगा। यह बात सिर्फ हमने ही बार-बार कही है। बाकी सारी वामपंथी पार्टियां इस प्रस्ताव का विरोध करती रही हैं, क्योंकि इन पार्टियों के साथ जमाखोरों और कालाबाजारियों की सांठगांठ रहती है। इनके पैसे से ही ये पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और लोग टीवी देखकर, अखबार पढ़कर इन पार्टियों के प्रचार से भ्रमित हो जाते हैं। बहुत दिन पहले ही कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा था कि जनता राजनीतिक तौर पर सचेत नहीं है, संगठित नहीं है। बुर्जुआ मीडिया हवा बनाता है और पूंजीपतियों की मदद से पार्टियां पैसे लूटाती है और उसी हवा में जनता तिनकों की तरह उड़ जाती है। यह चुनाव वास्तव में एक प्रहसन ही है। यह बुर्जुआ मीडिया हवा बनाता है कि इस बार किसकी ताकत ज्यादा है, कौन जीतेगा, कौन किसे हराएगा, इसलिए उसे ही वोट देना है। वे कभी कांग्रेस को, कभी सीपीआई(एम) को, कभी तृणमूल को, तो कभी भाजपा को आगे बढ़ाते हैं और टीवी पर तथा अखबारों में उनका बड़े पैमाने पर प्रचार करते हैं। राजनीतिक तौर पर अचेत, असंगठित और दो-चार पैसे कमाने के लिए दिन भर काम करने वाले थके-हारे आम लोग भी सोचते हैं कि इतने दिनों तक तो इनको देखा, इस बार उनको देखते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर वे कहेंगे कि इन्हें तो एक बार देख लिया, इस बार उन्हें देखते हैं। यही बार-बार होता है। 1952 से लेकर आज तक इस देश में बार-बार चुनाव हुए हैं और बीच-बीच में सरकार में बदलाव भी हुआ है। लेकिन आम लोगों को क्या मिल रहा है? उल्टे जीवन के सभी क्षेत्रों में चौतरफा संकट बढ़ रहा है। नेता जनता की सेवा में कितने तत्पर हैं, यह दिखाने के लिए वे चुनाव से पहले तरह-तरह के आश्वासन और प्रलोभन देते हैं। फिर सबकुछ मिट्टी में मिल जाता है। सवाल पूछने पर कहते हैं कि चुनाव के समय यह सब कहना पड़ता है। जनता भी उम्मीद लगाती है, फिर हताश होकर कहती है कि जो लंका में जाता हैं, वही रावण बन जाता है। यही लंबे समय से चल रहा है। इसी के चलते कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा था कि चुनाव और क्रांति एक चीज नहीं है। चुनाव से सरकार बदलती है और क्रांति से शोषणमूलक राजसत्ता और आर्थिक व्यवस्था बदलती है। फलस्वरूप जनजीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए और शोषण से मुक्ति पाने के लिए चुनाव नहीं, बल्कि क्रांति चाहिए। बहुत दिन पहले ही यह बात उन्होंने कही थी। हमारी पार्टी आज भी इसी बात को मानकर चल रही है।

यही एकमात्र पार्टी है, जिसे कभी खरीद नहीं सकते हैं पूंजीपति

फिर यह बात भी सही है कि हम चुनाव लड़ते हैं। महान लेनिन ने कहा है कि क्रांतिकारी तब तक चुनाव लड़ते हैं, जब तक लोगों में चुनाव का मोह बना रहता है। चुनाव के जरिये संसद में जाकर लोगों की समस्याओं का सही में कोई समाधान संभव नहीं है। यह दिखाने के लिए क्रांतिकारी पार्टियों को चुनाव में शामिल होना चाहिए। लेकिन लेनिन ने यह नहीं देखा था कि किसी बुर्जुआ राजसत्ता के अंदर ही कोई क्रांतिकारी पार्टी एक विशेष देश की विशेष परिस्थिति में एक घटक के तौर पर सरकार में शामिल भी हो सकती है। फलस्वरुप यह परिस्थिति पैदा होने पर क्या करना है, यह सीख उन्होंने नहीं दी थी। 1967 में भ्रष्ट कांग्रेस को हटाकर पश्चिम बंगाल के लोगों ने जब संयुक्त मोर्चे को जिताया, तब उस संयुक्त मोर्चे में हम और कुछ अन्य वामपंथी पार्टियां भी थीं। जब सरकार गठन का सवाल आया, तब लेनिन की इस सीख को और विकसित करते हुए कांग्रेस शिवदास घोष ने कहा था कि संयुक्त मोर्चा सरकार का काम होगा सरकार के पास जितने भी पैसे हैं, उनका गरीबों के हित में इस्तेमाल करना। साथ ही यह सरकार मजदूरों के वर्ग-संघर्ष, किसानों के वर्ग-संघर्ष और जन आंदोलन को और तेज करने में मदद करेगी, उन्हें पुलिसिया हमले से बचाएगी। कॉमरेड शिवदास घोष के इस गाइडेंस का सीपीआई(एम), सीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, बांग्ला कांग्रेस–सभी ने भारी विरोध किया। तब उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। इसके मात्र कई साल पहले डांगे को संशोधनवादी कहते हुए 'क्रांति करेंगे' के नारे के साथ कार्यकर्ताओं को अपनी ओर खींचकर सीपीआई से सीपीआई(एम) अलग हुई थी। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में तब भी क्रांति के प्रति चाह थी। नेताओं ने देखा कि अगर इस सवाल पर वे हमसे एका तोड़ेंगे, तो यह उनके लिए खतरा पैदा करेगा। उनके कार्यकर्ता सवाल उठाएंगे। नतीजतन वे मान गये। उन्होंने सोचा कि एसयूसीआई छोटी पार्टी है, वह कुछ नहीं कर पायेगी। उन्होंने हमें परेशानी में डालने के लिए हमें श्रम मंत्रालय दिया। कॉमरेड शिवदास की सीखों के आधार पर श्रम मंत्री के रूप में कॉमरेड सुबोध बनर्जी ने यह घोषणा की कि संयुक्त मोर्चा सरकार मजदूर वर्ग के आंदोलन, जन आंदोलन को पुलिस द्वारा दमन नहीं करेगी। पूरे भारत के पूंजीपतियों ने आतंकित होकर यह मांग की कि एसयूसीआई को सरकार से, मंत्रिमंडल से हटाओ। उनके दबाव में केन्द्र सरकार ने पहली संयुक्त मोर्चा सरकार तोड़ दी। इसके बाद 1969 में जब फिर दूसरी संयुक्त मोर्चा का जब गठन हुआ, तब पूंजीपतियों के दबाव में हमसे श्रम मंत्रालय छीन लिया गया। यह सब अतीत के इतिहास हैं। इन्हें आपको जानना है।

आज भी हम कॉमरेड शिवदास घोष की इसी सीख के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हमें एक भी वोट न मिले, एक भी सीट न मिले, फिर भी हमारी पार्टी क्रांतिकारी लाइन पर ही चलेगी। आप सभी जानते हैं, भारत की जनता जानती है कि जहां कहीं भी हम चुनाव लड़ते हैं, वहां हम अपने उम्मीदवार के पर्चे भरने की राशि भी हम लोगों के घर-घर जाकर, सड़कों पर खड़े होकर चंदे से इकट्ठा करते हैं। यह काम सिर्फ यही एक पार्टी करती है। आज की इस जनसभा के लिए भी कोलकाता शहर में, पश्चिम बंगाल के शहरों में, गांवों में, हमारे कार्यकर्ता घर-घर जाकर, सड़कों पर खड़े होकर चंदा इकट्ठा किया है। यही एक ऐसी पार्टी है, जिसे अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला खरीद नहीं पाये हैं, खरीद भी नहीं पायेंगे। हम गरीबों की पार्टी हैं। गरीबों की मदद से ही हम पार्टी चलाते हैं। चुनाव भी हम उसी तरह से लड़ते हैं। 2001 में सीपीआई(एम) ने हमें मंत्रिमंडल में शामिल होने का ऑफर दिया था। हमने ठुकरा दिया। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने हमें सीटे देने का प्रस्ताव दिया था। हमने ठुकरा दिया। यह पार्टी मंत्री पद के लिए नहीं है, यह पार्टी एमएलए, एमपी के लिए नहीं है। हमारी पार्टी की तरक्की मंत्रिओं दम पर नहीं हुआ है, सरकार के दम पर नहीं हुआ है, एमएलए-एमपी के दम पर नहीं हुआ है, मीडिया प्रचारों के दम पर भी नहीं हुआ है।

आप लोग जानते हैं कि 1948 में कॉमरेड शिवदास घोष ने दक्षिण 24 परगना के जयनगर शहर के एक छोटे-से हॉल से मात्र 7 सहयोद्धाओं और थोड़े-से कार्यकर्ताओं को लेकर इस पार्टी का सफर शुरू किया था। तब इस पार्टी का नाम भी कोई नहीं जानता था। किसी भी अखबार ने इस पार्टी के बारे में लोगों को नहीं बताया। ऐसा वे आज भी नहीं करते हैं। आज तो सीपीएम कमजोर हो गयी है, चुनाव में पस्त हो चुकी है। उन दिनों संयुक्त सीपीआई काफी ताकतवर पार्टी थी। महान स्तालिन और महान माओ-त्से तुंग उनका समर्थन करते थे। पूरे भारत में उनका जबरदस्त प्रभाव था। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक भी एक बड़ी पार्टी थी। अनुशीलन समिति के समर्थन के बल पर आरएसपी, सौमेन ठाकुर द्वारा स्थापित आरसीपीआई–सभी बड़ी पार्टियां थीं। उन्होंने कॉमरेड शिवदास घोष को लेकर कितने मजाक उड़ाये, कितने व्यंग्य किये। वे कहा करते थे कि कुकुरमुत्ते उग आये हैं। यह कोई पार्टी नहीं है, यह तो क्लब है। उन दिनों कॉमरेड शिवदास घोष ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप रहकर उन्होंने सबकुछ सहा और इस पार्टी को खड़ा करने के लिए कठिन-कठोर संघर्ष चलाया। उन दिनों कॉमरेड शिवदास घोष के पास कोई स्थाई ठौर-ठिकाना नहीं था। उन्होंने फुटपाथों पर, पार्कों में, कोले मार्केट की छत पर, स्टेशन के प्लेटफार्म पर रातें बितायी। वे कितने ही दिन भूखे रहे। उन्होंने खुद ही एक भाषण में कहा था कि ऐसे भी दिन थे, जब हम दो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाये। आज हम इतनी बड़ी जनसभा कर रहे हैं, मंच पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जबकि कॉमरेड शिवदास घोष एक-एक कार्यकर्ता इकट्ठा करने के लिए मीलो पैदल चलते थे।

मैं 1950 में पार्टी के साथ जुड़ा और मेरे सहकर्मी कॉमरेड असित भट्टाचार्य कुछ दिनों के बाद जुड़े। हमने भी कॉमरेड शिवदास घोष को भूखे रहते देखा है। हम स्कूल में मीटिंग कर रहे थे, वहां पहुंचने में कॉमरेड शिवदास घोष को कुछ देर हो गयी। बाद में पता चला कि कॉमरेड शिवदास घोष और कॉमरेड निहार मुखर्जी के पास एक ही कमीज थी। जो बाहर निकलते थे, वे उसे पहनते पहनते थे। कॉमरेड निहार मुखर्जी के लौटने में देर होने की वजह से उस दिन उन्हें आने में विलंब हुआ था। उन दिनों जो लोग कॉमरेड घोष का मजाक उड़ाया करते थे, वह फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, सीपीआई आज कहां है? सीपीआई(एम) भी आज कहां है? हमारी पार्टी आज लगातार आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई इलाका नहीं है, जहां आदरपूर्वक हमारी पार्टी का नाम नहीं लिया जाता है। कॉमरेड शिवदास घोष का नाम भी आदरपूर्वक लिया जाता है। एक दिन जिस पार्टी का उन्होंने क्लब कहकर व्यंग्य किया था, आज की तारीख में भारत के 23 राज्यों में उस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और समर्थक कॉमरेड शिवदास घोष की तस्वीर के साथ लाल झंडा फहराकर स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारी पार्टी महान मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष के विचारों की अमोघ शक्ति से लैस होकर लगातार बढ़ती जा रही है। जब तक हम यह सोच लेकर चलते रहेंगे, तब तक हम ताकतवर बने रहेंगे।

नीति-सिद्धांतहीन राजनीतिक नेता युवाओं को बना रहे हैं अपराधी

आज चुनाव सभी देशों में एक प्रहसन में तब्दील हो चुका है। एक और भयानक चीज

(शेष पृष्ठ 5 पर)

सीपीआई(एम) की गैर वामपंथी राजनीति ने भाजपा के उभरने का बना दिया है रास्ता

कॉमरेड प्रभास घोष का भाषण..

(पृष्ठ 4 का शेष)

भी हो रही है। एक ओर लोगों को भिखारी बनाकर, भूखे रखकर, एक मुट्ठी अनाज और कुछ पैसे देकर ये सभी पार्टियां अपने वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल कर रही हैं, तो दूसरी ओर वे पूरे देश में अपराधियों का एक सशस्त्र गिराह तैयार कर रहे हैं। बेरोजगार युवा, जिनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उनमे असंतोष और विक्षोभ की आग न भड़क उठे, इसलिए उन्हें ये पार्टियां शराब पीने, जुआ खेलने, सट्टेबाजी करने, छिनतई करने, डकैती करने आदि के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वे कहती हैं कि डर की कोई बात नहीं है। सत्ताधारी पार्टी तुम्हारी रक्षा करेगी। और इसी वजह से इन युवाओं के विवेक और इन्सानियत को यह पूंजीवाद और पूंजीवाद की सेवक ये पार्टियां बर्बाद कर रही हैं। वे इन्सानियत की जान यौवन को ध्वस्त कर रही हैं, उन्हें हैवान बना रही हैं। अश्लील फिल्मों, ब्लू फिल्मों, फिल्मी सितारों की गंदी पंकिल कहानियों, अश्लील साहित्यों और शराब का ध ड़ल्ले से कारोबार चल रहा है। इस राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो मोहल्ले-मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल रही है। अब तो सुन रहा हूं कि वे दरवाजे पर शराब पहुंचाएंगे। यह सिर्फ सरकार की कमाई के लिए नहीं है। पैसा कमाने का मकसद तो है ही, साथ ही युवाओं को मदहोश बनाकर रखना भी उनका मकसद है। इसके साथ-साथ जारी है गंदी यौनता, महिलाओं की देह को लेकर चर्चाएं, महिलाओं को देखते मात्र उन पर हमला बोल देना। यही वजह है कि रोजाना इतने सारे बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। कितनी महिलाओं की चीख-पुकार, उनके विरोध की आवाज को कुचलकर उन्हें मार दिया जाता है। छः साल की बच्ची से लेकर 70 साल की बुजुर्ग महिला तक–कोई भी बलात्कार का शिकार होने से बच नहीं पा रहा है। यही तो देश का विकास है। ऐसी हालत पैदा हो गयी है कि बेटी अपने बाप पर बलात्कार का आरोप लगा रही है। क्या कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार के जयगान से, 'अच्छे दिन' के सफर के मंत्र या हिन्दुत्ववाद और रामनवमी की ध ार्मिक हुंकार से इन हजारों बलात्कार की शिकार महिलाओं, पीड़िताओं की चीख-पुकार दब जायेगी? अगर राममोहन, विद्यासागर, रवीन्द्रनाथ, विवेकानन्द, शरतचंद्र, नजरूल, देशबंधु सीआर दास, सुभाषचन्द्र बोस यह हालत देखते, तो क्या कहते? आज बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, खून खराबा आदि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। युवाओं को अपराधी बनाया जा रहा है। दरअसल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि क्रिमिनलाइजेशन बाय द पॉलीटिशियन हो रहा है। पूरे भारत में ऐसा चल रहा है। ये लोग शारीरिक रूप से तो इन्सान हैं, लेकिन स्वभाव से विवेकहीन हैं, न्याय-अन्याय बोध विहीन हैं, इन्सानियत विहीन हैं। ये लोग जानवरों से भी बदतर हैं। आज भारत में हर जगह मोहल्ले-मोहल्ले में यह जो भयानक स्थिति है, यह पूंजीवाद की सेवक इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तैयार की गयी है। यही लोग मतदान के दौरान कागजात छीन लेते हैं। यही लोग रिगिंग करते हैं। यही लोग मोहल्लों में चुनाव के दौरान लोगों को धमकियां देते हैं। वे कहते हैं कि आपको वोट देने नहीं जाना है, हम आपका वोट दे देंगे या फिर अगर आप उस पार्टी को वोट देंगे, तो आपका इस मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जायेगा। इस प्रकार एक ओर ये सारी पार्टियां यह तथाकथित 'विकास यात्रा' चला रही हैं, तो दूसरी ओर खून खराबे, घरों में बंद कर महिलाओं को जलाकर मार डालने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल के बीच होड़ लगी है। मंत्रियों की मानसिकता ऐसी है कि जैसे यह सब कोई घटना ही नहीं है, ये तो बहुत ही तुच्छ चीजें हैं। जैसे भी हो अपनी जिम्मेदारी से पिंड छुड़ा लेने से ही वे खुश हैं। जरा-सी भी दुख-तकलीफ व पश्चाताप नहीं है, प्रतिकार की बात तो दूर।

एक और खतरनाक घटना यह है कि हर स्तर पर भ्रष्टाचार ही नीति बन गयी है। सबसे ऊपरी स्तर से लेकर सबसे निचले स्तर तक, केन्द्र या राज्य किसी भी सरकार में बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं होता है। जैसे कि यही इस देश का अलिखित कानून है। हाल ही में आपने देखा कि भाजपा शासित कर्नाटक में एक ठेकेदार ने एक मंत्री के विरुद्ध पत्र लिखकर आत्महत्या कर ली है। प्रधानमंत्री तक को जानकारी देने के बावजूद उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। मंत्री ने 40% कमीशन की मांग की थी। हिन्दू धर्म के झंडाबरदार भाजपा के शासन में किस तरह से 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' चल रहा है, इसी से आप समझ सकते हैं। हर राज्य में ठेका पाने के लिए मंत्री-नेताओं को सलामी देनी पड़ती है। उसके बाद बिल पास कराते वक्त कमीशन देना पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस शासित इस राज्य में भी शिक्षक की नौकरी के लिए लाखों रुपये रिश्वत देनी पड़ी है। अब मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा इस राज्य में तोलाबाजी (हप्ता वसूली), सिंडिकेट राज–यह सब तो बेरोकटोक चल ही रहा है। आपसी बंटवारे को लेकर तृणमूल कांग्रेस द्वारा संरक्षणप्राप्त अपराधियों की झड़पों में खून-खराबा भी हो रहा है। इसके अलावा, महिलाओं और बच्चियों की तस्करी की घटनाएं तो हैं ही।

वे एक और बर्बादी ला रहे हैं। वे गरीबों को भी भ्रष्ट बना रहे हैं। 100 दिनों के बदले 20-30 दिन काम कराकर ज्यादातर पैसा नेता लोग अपनी जेबों में भर रहे हैं और गरीबों को थोड़ा कुछ दे रहे हैं। वृक्षारोपण, तालाब बनाने के नाम पर यह सब चल रहा है। नेता-मंत्री तो भ्रष्ट हैं ही, इस तरह से गरीबों को भी बिना काम का, या थोड़ा-सा काम देकर, मजदूरी देकर वे भ्रष्टाचार में शरीक कर रहे हैं। केन्द्र और राज्य सरकारें जो पैसा मुहैया कराती हैं, इस तरह से मंत्री और नेता हर स्तर पर अपनी जेबें भर रहे हैं। गृह निर्माण योजना में अगर तीन लाख रुपये मुहैया होता है, तो उसका आधा ऊपर वालों को देना पड़ता है। हर स्तर पर यही चल रहा है और जनता भी इसी को स्वभाविक मान रही है। कानून अपने रास्ते पर नहीं चलता है, बल्कि सरकारी पार्टियों के इशारे पर चलता है। जिस तरह से केन्द्र में सीबीआई और ईडी भाजपा का हुक्म तामील कर रही है, उसी तरह इस राज्य में थाना-पुलिस तृणमूल कांग्रेस के निर्देश पर चलता है। सरकारी पार्टियों के खाते में नाम रहने से हजार खून माफ हो सकता है और विरोध करने पर हमेशा सिर पर तलवार लटकती रहती है। 'सुशासन', 'अच्छे दिन', 'सरकार आपके द्वार', 'दीदी से कहो'–यह सब सिर्फ विज्ञापन तक ही सीमित है।

मार्क्सवाद से भटक चुकी सीपीआई(एम) ने खो दिया है जनसमर्थन

पश्चिम बंगाल में यह सब 1972 में सिद्धार्थ राय के कांग्रेस के शासन के दौरान शुरू हुआ था। बाद में यह और भी बड़े पैमाने पर तथाकथित मार्क्सवादी सीपीआई(एम) के शासन में शुरू हुआ। पंचायत से लेकर हर जगह यही सब हो रहा है। सीपीआई(एम) ने पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों तक शासन कर पश्चिम बंगाल के यौवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 34 वर्षों तक राज करने के बाद चुनाव में तो वे हार ही रहे हैं, अब वे इस बात को लेकर संतोष जाहिर कर रहे हैं कि उनके वोट का प्रतिशत कितना बढ़ा है।

हालांकि इसी पश्चिम बंगाल में एक वक्त वामपंथ का बोलबाला था। यहां संयुक्त बंगाल में युगांतर और अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी संगठनों का जन्म हुआ था। यहीं सशस्त्र क्रांतिकारी धारा के सेनानी खुदीराम से लेकर बाघा जतिन, विनय, बादल, दिनेश, प्रीतिलता, सूर्य सेन और भी बहुतों का जन्म हुआ था। बाद में जिनके प्रतिनिधि के रूप में गैर समझौतावादी धारा के सशक्त प्रतिनिधि सुभाषचन्द्र बोस उभरकर सामने आये। कांग्रेस के गांधीवादी दक्षिणपंथी थे, जबकि सुभाषचन्द्र बोस वामपंथी थे। इस वामपंथ के प्रति पश्चिम बंगाल में जो जज्बात था, सोवियत यूनियन तथा चीन के समाजवाद की विजययात्रा और उसका जो जबरदस्त प्रभाव था, उसी के आधार पर संयुक्त सीपीआई ने एक समय ताकत हासिल किया था। लेकिन कॉमरेड शिवदास घोष ने आजादी आंदोलन में सीपीआई की भूमिका को देखकर यह समझ लिया था कि मार्क्सवाद का नाम लेने पर भी यह पार्टी दरअसल मार्क्सवादी पार्टी के रूप में विकसित ही नहीं हुई है। जिस तरह लेनिन ने कहा था कि एंगेल्स के द्वारा स्थापित दूसरे इंटरनेशनल ने क्रांति के झंडे को छोड़ दिया है, इसलिए तीसरा इंटरनेशनल चाहिए। लेनिन ने भी कहा था कि रूस में तथाकथित मार्क्सवादी आरएसडीएलपी सही मार्क्सवादी पार्टी नहीं है, इसलिए बालशेविक पार्टी का निर्माण करना होगा। कॉमरेड शिवदास घोष ने भी पूरे आजादी आंदोलन के दौरान सीपीआई के रवैये को देखकर यह समझ लिया था कि यह पार्टी सही मार्क्सवादी पार्टी नहीं है। फलस्वरुप भारत की धरती पर एक सही क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी का गठन करना होगा। यहां अगर सीपीआई(एम) के कोई कार्यकर्ता या समर्थक हों, तो उन्हें मैं यह सोचने के लिए कहूंगा कि इस बंगाल की जनता के अंदर एक समय आप लोगों का कितना प्रभाव था। किस तरह से एक के बाद एक गैर मार्क्सवादी आचरण से आज आप लोग इस जगह पर पहुंचे हैं, जहां कितना प्रतिशत वोट मिल रहा है, यही आप लोगों के लिए आत्म संतुष्टि का विषय हो गया है।

सीपीआई(एम) की गैर वामपंथी राजनीति ने भाजपा के उभरने का बना दिया है रास्ता

आपको कुछ घटनाओं की याद दिलाना चाहूंगा। भारत के आजादी आंदोलन के दौरान महान स्तालिन ने कहा था कि बड़े बुर्जुआ लोग यानी कांग्रेस का गांधीवादी नेतृत्व साम्राज्यवाद के साथ समझौता कर रहा है। भारत के कम्युनिस्टों को चाहिए कि वे मध्यमवर्गीय क्रांतिकारियों के साथ एकजुट हों और बड़े बुर्जुआ नेतृत्व को आजादी आंदोलन के नेतृत्व से अलग-थलग कर दें। जैसा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ-त्से तुंग के नेतृत्व में किया था। भारत की तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टी ने महान स्तालिन की इस सीख का कभी अनुसरण नहीं किया। जब कांग्रेस के अंदर एक ओर बड़े बुर्जुआ के प्रतिनिधि गांधीवादी और दूसरी और सुभाषचन्द्र बोस का गैर समझौतावादी नेतृत्व था, सीपीआई ने गांध ीवादियों के समर्थन में ही खड़े होकर सुभाषचन्द्र बोस का विरोध किया था। एक वक्त यह मौका था, यह अवसर मिला था कि सुभाषचन्द्र बोस को सामने रखकर राष्ट्रीय कांग्रेस में ही वामपंथी नेतृत्व की स्थापना की जाये। लेकिन ये लोग त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाषचन्द्र के समर्थन में खड़े नहीं हुए था, बल्कि इन्होंने गांध ीवादियों का समर्थन किया था। वेलिंगटन स्क्वायर में सुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए थे। इसके बाद भी उन्होंने रामगढ़ के अधिवेशन में सीपीआई से आह्वान किया था कि आइए, हम सभी वामपंथी एकजुट हो जायें। वहां भी उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। इन बातों को आपको जानना है।

आप में से बहुतों को शायद यह नहीं पता हो कि हिन्दू महासभा ही सबसे पहले हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का प्रस्ताव लायी थी। उन्होंने कहा था कि हिन्दू एक अलग राष्ट्रीयता है, जबकि मुसलमान एक अलग राष्ट्रीयता। मुस्लिम लीग ने भी ऐसी ही मांग उठायी थी। आप यह सुनकर दंग रह जायेंगे कि तथाकथित मार्क्सवादी पार्टी सीपीआई ने भी इसी हिन्दुस्तान- पाकिस्तान के सिद्धांत का समर्थन किया था। 1942 का अगस्त आंदोलन इतना बड़ा था, लेकिन सीपीआई उसके खिलाफ हो गयी। उसने नारा दिया कि अंग्रेज साम्राज्यवादियों के साथ सहयोग है। सुभाषचन्द्र बोस ने कभी फासीवाद का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने जर्मनी द्वारा सोवियत पर हमले की निंदा भी की थी। उन्होंने रणनीति के तहत जापान की मदद से आजाद हिंद सेना का गठन किया था। वह रणनीति सही थी या नहीं–इस पर बहस हो सकती है। लेकिन वह क्या इसलिए कि जापान भारत पर कब्जा जमा ले? 10 जनवरी 1942 को सीपीआई ने अपने मुखपत्र 'पीपल्स वार' में सुभाषचन्द्र बोस को जापान का दलाल और क्विसलिंग कहा था। उसने कहा था कि उन्हें हम देशद्रोही के रूप में देखेंगे। बाद में भी

(शेष पृष्ठ 7 पर)

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2021-23
Posting at DPSO, Delhi -06 on 07–08 and 22–23 of every month, Fortnightly , Date of Publication: June 5, 2022

हरियाणा में मिड-डे मील कार्यकर्ताओं के आंदोलन की शानदार जीत

स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ऑल इडिया कमेटी की प्रेसिडेंट टीसी रमा और महासचिव इस्मत आरा खातून ने हरियाणा की मिड-डे मील कार्मियों को उनके मेहनताने में दुगुनी बढ़ोतरी होने पर बधाई देते हुए 28 मई को एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा :

साथियों,

हरियाणा में मिड-डे मील कुक कम हेल्परों का मानदेय बढ़ा। ऑडर के अनुसार यह 3500 रुपये प्रति माह से बढ़कर अब 7000 रुपये प्रति माह हो गया है। यह मिड-डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा संबंधित एआईयूटीयूसी व स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले चले आंदोलन की शानदार जीत है। इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत बध इयां। हालांकि यह आंशिक जीत हासिल हुई है, आगे और लड़ाई है।आप इस आंदोलन को और आगे ले जाएं। पुरी जीत आपकी होगी।लड़ेंगे और जीतेंगे।

बधाई के साथ।

मिड-डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा संबंधित एआईयूटीयूसीके बैनर तले 1 जून को भिवानी में विजय जुलूस निकालते हुए मिड-डे मील कार्यकर्ता

किसानों का धरना

अशोकनगर (म.प्र.) : किसानों की तमाम उपज पर एमएसपी की गारंटी की मांग पर व खेती में इस्तेमाल होनेवाली बिजली को मंहगा किये जाने के खिलाफ 30 मई को मध्य प्रदेश के अशोकनगर में अम्बेडकर पार्क पर एआईकेकेएमएस के तत्वावधान में किसानों ने धरना दिया। धरने में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए।

धरने को संबोधित करते हुए एआईकेकेएमएस के राज्य सचिव कॉमरेड मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि हाल ही में सरकार कृषि में उपयोग होनेवाली बिजली पर से कथित सब्सिडी समाप्त करने की योजना बना रही है। इसमें कहा जा रहा है कि किसानों को एक साथ पूरा पैसा जमा करना होगा। इसके बाद बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी का पैसा किसानों के खातों में वापस किया जायेगा। यह किसानों के साथ कोरा छलावा है। किसान जानता है कि जिस ढंग से रसोई गैस पर मिलनेवाली सब्सिडी को धीरे-धीरे खत्म कर दिया गया, उसी तरह सरकार बिजली पर मिलनेवाली सब्सिडी को खत्म करना चाहती है।

धरने को एआईकेकेएमएस के जिलाध्यक्ष कॉ. मोहनसिंह यादव गुचराई तथा एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) जिला सचिव कॉ. सचिन जैन ने भी संबोधित किया। धरने के उपरांत एक प्रतिनिमिंडल द्वारा ग्राम गनियारी की समस्याओं सहित अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश महोदय को सौंपा गया। धरना सभा का संचालन संगठन

धरना को संबोधित करते हुए एआईकेकेएमएस राज्य सचिव कॉ. मनीष श्रीवास्तव

कोल्हान विश्वविद्यालय के विशिष्ट छात्र नेता रमेश डेनियल की स्मृति सभा

एआईडीएसओ पश्चिमी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से रमेश डेनियल की स्मृति सभा 29 मई को दिव्या भारती हॉल चाईबासा में सम्पन्न हुई।

इस मौके पर बतौर मुख्य वक्ता एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की राज्य कमेटी सदस्य कॉ. लिली दास उपस्थित थीं। इसके अलावा इप्टा सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष कैसर परवेज, सोनुवा के पंचायत मुखिया तथा समाजिक कार्यकर्ता डॉ. दिनेश चन्द्र बोइपाई, जोहार चाईबासा के कॉन्वेनर रमेश जेराई, एआईडीएसओ की राज्य अध्यक्षा कॉ. आशा रानी पाल, एआईडीएसओ राज्य सचिव कॉ. समर महतो, युवा संगठन एआईडीवाईओ से कॉ. रूपा सरकार, श्रमिक संगठन एआईयूटीयूसी से कॉ. विष्णु देवगिरी, किसान संगठन एआईकेकेएमएस से कॉ. आशुदेव महतो, महिला संगठन एआईएमएसएस से कॉ. मौसमी मित्रा आदि उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि विगत 1 मई को सड़क दुर्घटना में कॉमरेड रमेश डेनियल का आकस्मिक निधन हो गया था। रमेश डेनियल एआईडीएसओ के राज्य सचिवमंडल सदस्य और पश्चिम सिंहभूम के जिला प्रभारी थे। आपने छात्र राजनीति की शुरुआत घाटशिला कॉलेज से की। जब आप घाटशिला कॉलेज इकाई के अध्यक्ष थे, तब आप कॉलेज के विभिन्न मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहते थे। आपने पिछले ही वर्ष विश्वविद्यालय से फिजिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की थी। आपने कॉलेज में व्याप्त शैक्षणिक समस्याओं और मुद्दों को लेकर छात्र आंदोलन का निर्माण किया व कई ऐतिहासिक जीत भी दिलाई। झारखंड में छात्रवृत्ति में कटौती के खिलाफ छात्रवृत्ति आंदोलन को सफल बनाने में और साथ ही 2020 में छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल पुनः चालू करने की मांग को लेकर हुए ऐतिहासिक छात्र आंदोलन की जीत में भी आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही। आपके गहन चिंतन और संगठन विस्तार के लिए आपके दूरगामी सोच ने अनेक लोगों को प्रभावित किया। आपके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि झारखंड के कई प्रमुख क्षेत्र और जिलों में संगठन को निचले स्तर से खड़ा किया जा सका। वर्तमान में कोल्हान प्रमंडल स्थित कोल्हान यूनिवर्सिटी के प्रमुख छात्र नेता के रूप में आप यूनिवर्सिटी स्तरीय छात्र मुद्दों को उठाते रहे हैं। कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों से प्रभावित होकर आपने झारखंड राज्य में कई प्रमुख मुद्दों को लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया। आपके असामयिक निधन से केवल एआईडीएसओ संगठन को ही नहीं, बल्कि छात्र आंदोलन को गहरी क्षति हुई है।

कॉ. रमेश डेनियल लाल सलाम

कॉमरेड संजय पराशर लाल सलाम

हरियाणा के सोनीपत में एसयूसीआई (सी) की गांव नाहरी लोकल कमेटी के सदस्य कॉमरेड संजय पराशर का 15 मई को निधन हो गया। कॉ. संजय पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता व हमदर्द थे और गंभीर रूप से बीमार होने तक पार्टी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। गांव नाहरी स्तर पर कॉ. संजय काफी सक्रिय रहते थे।

नाहरी में पार्टी द्वारा संचालित शहीद भगतसिंह मेमोरियल स्कूल में उन्होंने कई साल तक बेहद कम वेतन पर बच्चों को पढ़ाया था। सीधे-सादे स्वभाव वाले कॉमरेड संजय को गांव में संजय मास्टर के नाम से जाना जाता था।

कॉ. संजय पराशर की असामयिक मौत पर 25 मई को एक शोक सभा की गयी। शोक सभा को पार्टी के हरियाणा राज्य सचिवमंडल सदस्य कॉ. ईश्वर सिंह राठी, पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य और एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव कॉ. हरि प्रकाश और पार्टी के सोनीपत जिला सचिव कॉ. इंदर सिंह ने श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन-संघर्ष पर प्रकाश डाला। संचालन पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य कॉ. वीरेन्द्र सिंह दहिया ने किया।

कॉमरेड संजय पराशर लाल सलाम।

किसानों का प्रमंडलीय कन्वेंशन आयोजित

मुजफ्फरपुर (बिहार) : खेती और किसानों की समस्याओं को लेकर एआईकेकेएमएस सहित 8 किसान संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में 2 जून को बिहार के यहां प्रमंडल स्तरीय किसान कन्वेंशन आयोजित किया गया। कन्वेंशन में प्रमंडल, राज्य एवं केन्द्रीय स्तर के नेताओं ने भाग लिया। विस्तृत व सारगर्भित चर्चा के बाद किसान खेत मजदूरों का एक मजबूत संयुक्त आंदोलन संगठित करने की योजना बनी।

कन्वेंशन के मंच पर उपस्थित किसान नेता

कॉमरेड प्रभास घोष का भाषण..

(पृष्ठ 5 का शेष)

पटेल प्रतिक्रियावादी हैं, नेहरू प्रगतिवादी हैं–ऐसी बातें उन्होंने कहीं। इसी मैदान में बहुत बार कॉमरेड घोष ने यह चर्चा की और दिखाया कि 1947 में ही पूंजीवाद सत्ता पर काबिज हो गया और भारत का पूंजीवाद सिर्फ पूंजीवाद नहीं है, वह एकाधिकार पूंजी का जन्म देकर साम्राज्यवाद में तब्दील हो चुका है। यहां क्रांति का स्तर है समाजवादी क्रांति। मूल ताकत है मजदूर वर्ग और गरीब किसान, जबकि मित्र है गरीब मध्यमवर्ग। हालांकि सीपीआई-सीपीआई(एम) का सिद्धांत है भारत में साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ जनता की जनवादी क्रांति (पीपल्स डेमोक्रेटिक रेवोलुशन करना)। मित्र कौन है? मित्र हैं राष्ट्रीय पूंजीपति, अमीर किसान, जोतदार वगैरह। हालांकि उनके कार्यकर्ता अब ऐसी सैद्धांतिक चर्चाओं में दिलचस्पी नहीं लेते हैं या किताबों को और नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद भी वे एक के बाद एक गैर मार्क्सवादी आचरण करते चले गये। उन्होंने कहा कि इंदिरा का कांग्रेस प्रगतिशील है, जबकि मोरारजी देसाई का कांग्रेस प्रतिक्रियावादी है। 1975 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में बड़े पैमाने पर जन आंदोलन का निर्माण हो रहा था, लोगों में महंगाई को लेकर रोष व्याप्त था, नौकरी आदि की मांग को लेकर छात्र-युवा वर्ग में गुस्सा फूट रहा था, बाद में जयप्रकाश नारायण के शामिल हो जाने पर, जिसे जेपी मूवमेंट कहा जाता है, वामपंथियों का नेतृत्व में न रहने के चलते उस आंदोलन का लाभ आरएसएस, हिन्दू महासभा, स्वतंत्र पार्टी आदि ने उठा लिया। कॉमरेड शिवदास घोष ने बार-बार सीपीआई(एम) और सीपीआई से कहा था कि इस आंदोलन की मांगें जनवादी हैं। जनता भी इस आंदोलन में शामिल है। आइए, हम वामपंथी लोग इस आंदोलन को नेतृत्व दें, दक्षिणपंथियों को अलग-थलग कर दें। ऐसा करने के लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं हुए। सीपीआई ने तो सरासर इंदिरा गांधी का समर्थन किया, जबकि सीपीआई(एम) ने भी परोक्ष रूप से समर्थन दिया। कॉमरेड घोष ने कहा कि आंदोलन में हम वामपंथियों के न रहने से इसका फायदा दक्षिणपंथी उठा रहे हैं। वे तैयार नहीं हुए। आज भाजपा की इतनी ताकत नहीं बढ़ सकती थी। उनकी ताकत बढ़ी जेपी मूवमेंट का फायदा उठाकर। इस आंदोलन में दक्षिणपंथी शामिल हैं, यह बहाना बनाकर सीपीआई(एम) इस आंदोलन में शामिल नहीं हुई। फिर 1977 में जब इन दक्षिणपंथियों ने जनता पार्टी का गठन किया, जिसमें आरएसएस और जन संघ भी था, तब चुनाव में उनकी जीत होगी, यह समझकर और यह जानते हुए भी कि इसमें जनसंघ और आरएसएस शामिल है, सीपीआई(एम) ने रातों-रात जनता पार्टी का समर्थन कर दिया। मोरारजी की सरकार को उन्होंने समर्थन दिया, जिसमें वाजपेई और आडवाणी मंत्री थे। इसी मैदान में ज्योति बसु और वाजपेई ने एक मंच से मीटिंग की है। बाद के समय में वीपी सिंह को भाजपा और सीपीआई(एम) ने संयुक्त रूप से समर्थन किया। एक के बाद एक यह सब उन्होंने किया है। कभी निरंकुश कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के साथ एकता, तो कभी साम्प्रदायिक भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के साथ एकता। यानी जहां जाने से चुनाव में सहूलियत होगी, एमएलए-एमपी की संख्या में बढ़ोतरी होगी, वे वहीं गये। (**जारी**)

नफरत की राजनीति के तमाशबीन क्यों बने हुए हैं प्रधानमंत्री?

(पृष्ठ 1 का शेष)

जहांगीरपुरी इलाके की घटना में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को नजरअंदाज करते हुए जिस तरह कई घंटों तक बुलडोजर चलाकर घरों, मकानों, दुकानों आदि को जमींदोज कर दिया गया, उसके पीछे सुनिर्दिष्ट राजनैतिक इरादा है। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे अपनी पार्टी की पहल से देशभर में पैदा हुए नफरत के इस माहौल को संकीर्ण दलगत राजनीति से ऊपर उठकर खत्म करने के लिए कदम उठायेंगे, यह उनसे उम्मीद है।

भाजपा-आरएसएस के नेतृत्व की ओर से सुनियोजित ढंग से अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने की घटना पर प्रधानमंत्री की खामोशी ने हर जागरूक इन्सान को चिंतित कर दिया है। कम से कम हिन्दुत्व के स्वयंभू रक्षकों को यह महसूस करने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि उनकी चुप्पी का मतलब ही है यह सब करने की इजाजत देना। नतीजतन, अल्पसंख्यकों पर हमले की वारदातें लगातार बढ़ी हैं और कभी-कभी वे पूरे देश के पैमाने पर हो रही हैं। हालांकि लोगों के जीवन की मुख्य ज्वलंत समस्याएं पहले से कहीं ज्यादा विकट हो गयी हैं, लेकिन इसके बावजूद इन समस्याओं को इससे पीछे धकेल दिया गया है। समस्याओं को हल करने में भाजपा सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए साम्प्रदायिकता फैलाकर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है।

आजादी आंदोलन के दौरान महापुरुषों ने अनेकता में एकता, धर्मनिरपेक्षता, साम्प्रदायिक सौहार्द आदि उन्नत विचारों के आधार पर देश में सांस्कृतिक आंदोलन गठित किया था, लेकिन यह सब आज बीते जमाने की बात होती जा रही है। बीजेपी-आरएसएस की बदौलत देश की मान-मर्यादा दुनिया की नजर में दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है। भाजपा-आरएसएस की इस साम्प्रदायिक राजनीति की वजह से भारत की ऐसी छवि बनती जा रही है कि मानो ज्यादातर भारतीय कट्टर हिन्दू हों, रूढ़िवादी और मुस्लिम-विरोधी हों। देश में विपक्षी राजनैतिक पार्टियों की निर्विरोधी मानसिकता, संकीर्ण चुनाव आधारित राजनीति के लिए साम्प्रदायिकता को प्रश्रय देने आदि की वजह से यह सोच भी पैदा हो रही है कि मानो देश की आम जनता हिन्दुत्ववादियों की ऐसी हिमाकत को चुपचाप बर्दाश्त कर रही हो। इसलिए देश के नागरिक कुछ निकम्मे, संवेदनहीन विपक्षी नेताओं के हाथों इस संगठित घोर अन्यायपूर्ण आचरण का प्रतिरोध करने की जिम्मेदारी सौंपकर चुप नहीं बैठे रह सकते। तब तो धर्मान्ध अतिवादी लोग इस खामोशी को अपनी सफलता के रूप में प्रचारित करेंगे। ऐसी स्थिति में पूर्व नौकरशाहों ने जिस भाषा में विरोध जताया है, वह बहुत ही आशाजनक है।

देश का शिक्षित समाज आज भी भाजपा-आरएसएस के हिन्दू राष्ट्र निर्माण का ख्वाब पूरे होने के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है। इसलिए यह नागरिक समाज भाजपा-आरएसएस के हमले का एक निशाना है। उनकी समर्थक सोशल मीडिया टीम और कारपोरेट घरानों द्वारा नियंत्रित टीवी चैनल भी जनता की नजर में इन लोगों को देश के दुश्मन के रूप में दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में नागरिक समाज सहित सभी तबकों के लोगों को भी विरोध में आगे आना चाहिए। देश को चलाने में सरकार की नाकामी, आकाशछूती महंगाई, बेरोजगारी, कानून को जबरन बेकार बना देने, सुनियोजित ढंग से दंगे भड़काना, धर्म के नाम पर पाखण्ड आदि तमाम बातें देश की जनता को हरगिज मंजूर नहीं हैं।

सोशल मीडिया के झूठे प्रचार, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के असत्य, फर्जी खबरों, दुष्प्रचार और इतिहास की तोड़-मरोड़ के खिलाफ शिक्षित समाज को हर मामले में सच्चाई को सामने लाने के लिए आगे आना चाहिए। आम लोगों के बीच ज्यादातर लोग, जो किसी धर्म के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते हैं, जो भाजपा के 'नये भारत' को नहीं मानते हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से वे लोग चुप रहने को मजबूर हैं, वे भी मुखर होंगे। शिक्षित समुदाय अगर हिम्मत के साथ इस तरह का विरोध प्रकट करेगा, तो आम आदमी भी अपनी आवाज बुलंद करेगा। इसलिए हर लिहाज से ही पूर्व नौकरशाहों द्वारा जताया गया यह विरोध देश के लिए बेहद अहम है।

आइए, विश्व पूंजीवाद–साम्राज्यवाद के खिलाफ मिलकर लड़ें

(पृष्ठ 3 का शेष)

साम्राज्यवाद न केवल समाज में समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, बल्कि अधिक से अधिक समस्याएं पैदा करता जा रहा है, जिनसे लोग मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हैं। हर देश में, देर-सबेर आनेवाली सर्वहारा क्रान्ति के बारे में शासकों को पूरा यकीन है। वस्तुनिष्ठ स्थितियां परिपक्व हैं, लेकिन व्यक्तिपरक तैयारी अभी बाकी है।

कोई आश्चर्य नहीं कि भारत में (जो कमोबेश सभी पूंजीवादी देशों के लिए सही होगा) हालिया सरकार ने मौजूदा 44 कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में एक साथ जोड़ने के नाम पर अधिकांश श्रमिकों को ट्रेड यूनियन अधिकारों और श्रम कानूनों के दायरे से लगभग बाहर कर दिया है। मालिकों के बेरहम शोषण और हायर एंड फायर को सुगम बनाने के लिए उन्हें पूरी तरह निहत्था कर दिया गया है।

वे हद दर्जे के धूर्त हैं। पूंजीपति वर्ग क्रांति को रोकने के लिए हर तिकड़म का सहारा ले रहा है। साझे दुश्मन के खिलाफ लोगों के एकजुट संघर्ष से बचने के लिए फूट डालो और राज करो की सदियों पुरानी रणनीति का सभी शासकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हम नस्लवाद की ताकतों का उभार देख रहे हैं, जैसा कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड और अन्य लोगों की निर्मम हत्या में दिखाई दिया, साम्प्रदायिक दमन और अल्पसंख्यकों की हत्या भारत में देखी गयी, पूरी दुनिया में क्षेत्रवाद, प्रांतवाद आदि को इस या उस रूप में सीधे तौर पर शासक वर्गों द्वारा सहायता देकर उकसाया जाता है।

इसके अलावा लोगों को पूरी तरह से भ्रम और अंधेरे में रखने के लिए तथा सच्चाई को छिपाने और झूठ फैलाने के लिए प्रचार के नये-पुराने तरीके इस्तेमाल किये जा रहे हैं। लेकिन अभी हम सूचना प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व विकास के युग में जी रहे हैं, जो एक ही समय में मानवता के लिए वरदान और अभिशाप है। निस्संदेह बड़ी मात्रा में ज्ञान भंडार मोबाइल फोन रखनेवाले किसी भी व्यक्ति के लिए उंगलियों पर उपलब्ध है। जरूरतमंदों को कुछ ही समय में प्रचुर मात्रा में जानकारी उपलब्ध होती है। लेकिन साथ ही, जानबूझकर झूठ और मिथकों को नेट में पोस्ट किया जाता है, विशेष रूप से विज्ञान, राजनीति और इतिहास के संबंध में, ताकि लोगों को सबसे महान और वैज्ञानिक विचारधारा मार्क्सवाद-लेनिनवाद से दूर किया जा सके। विभिन्न सोशल मीडिया साइटों का बदतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, चरित्र हनन और मार्क्स, लेनिन, स्तालिन और माओ-त्से तुंग जैसे महान विचारकों को बदनाम करने के लिए ताकि लोगों में ऑथोरिटी की भावना को नष्ट किया जा सके। इस कांग्रेस में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों और सभी देशों के मेहनतकश लोगों से हमारी विनम्र अपील है कि तार्किक ढंग से सत्य को असत्य से अलग करने के लिए गहराई से पढ़ें।

ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) की ओर से हम अपने पूर्व अध्यक्ष और एक महान मार्क्सवादी चिंतक कॉमरेड शिवदास घोष की महान शिक्षाओं को याद करना चाहते हैं, जिन्होंने मजदूर वर्ग के पहले शिक्षक कार्ल मार्क्स की महान शिक्षा को दोहराया है कि ट्रेड यूनियनें साम्यवाद के स्कूल हैं। निजी सम्पत्ति और वर्गों से मुक्त दुनिया की स्थापना के अपने साझे लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए विश्व सर्वहारा वर्ग के साथ जुड़ना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, ताकि पहले जनमानस से सभी भ्रमों को दूर करते हुए पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने और समाजवाद की स्थापना की दिशा में अपना रास्ता तैयार कर सकें। हम इस कांग्रेस के आयोजकों और प्रतिनिधियों से भी अपील करते हैं कि दुनिया के हर कोने में मौजूद विरोधी शक्तियों के खिलाफ एकजुट संघर्ष को तेज करने के लिए डब्ल्यूएफटीयू के इस मंच को मजबूत और व्यापक बनाया जाये।

डब्ल्यूएफटीयू जिंदाबाद!
सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद जिंदाबाद!
इंकलाब जिंदाबाद!
दुनिया के मजदूरों एक हो!

ऑनलाइन प्रतिनिधि: कॉ. राधकृष्ण, अध्यक्ष, कॉ. शंकर दासगुप्ता. महासचिव, एआईयूटीयूसी

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2021-23
Posting at DPSO, Delhi -06 on 07–08 and 22–23 of every month, Fortnightly , Date of Publication: June 5, 2022

राकेश टिकैत व अन्य किसान नेताओं पर बैंगलुरु में हुए फासीवादी हमले की निंदा

बैंगलुरु (कर्नाटक) :

ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) ने मीडिया रिपोर्ट में बताये अनुसार बैंगलुरु के एक कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह व संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ अन्य नेताओं पर 'मोदी, मोदी' के नारे लगाते हुए कथित भाजपाई गुंडों द्वारा किए गए फासीवादी हमले की निंदा की है। संगठन ने कहा कि यह केवल व्यक्तियों पर हमला नहीं है बल्कि भारत में लोकतंत्र की आकांक्षाओं पर जघन्य हमला है; यह केवल किसान नेताओं पर हमला नहीं है बल्कि उत्पीड़ित किसानों के संघर्ष की आवाज पर हमला है। यह उन लोगों की स्वतंत्र सोच पर एक फासीवादी हमला है, जो सरकार के सामने नहीं झुकते और सरकार-विरोधी और जन-परस्त सोच को प्राथमिकता देते हैं। यह विरोध के अधिकार पर हमला है। कारपोरेट कंपनियों और केंद्र व राज्य दोनों सरकारों की जनविरोधी नीतियों के कारण असहनीय हो गया है। महंगाई, गरीबी और भुखमरी से देश की मेहनतकश जनता, शोषित लोगों, छोटे व गरीब किसानों का जीवन जीना दूभर हो गया है। इस समय, जब लोग समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो सरकारें फासीवादी हमलों से लोगों में भय की मनोवृति पैदा कर रही हैं। समय आ गया है कि सभी वर्ग के मेहनतकश लोगों को जाति, पंथ और धर्मकर दीवारों को तोड़ते हुए जोरदार आंदोलन गठित करने चाहिएं।

साथ ही, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत व्यापक जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।

एच. वी. दिवाकर, अध्यक्ष,
कर्नाटक राज्य कमेटी,
एआईकेकेएमएस

पेट्रोल-डीजल व रसोई गैस लागत मूल्य पर उपलब्ध कराओ –एसयूसीआइ(सी)

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 22 मई को एक बयान जारी कर कहा:

''केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर करों में कमी की हालिया घोषणा वस्तुत: पिछले कई वर्षों के दौरान इनमें की गयी बेतहाशा बढ़ोतरी की तुलना में लगभग नगण्य है और इसलिए यह लाज बचानेवाले कदम के सिवा और कुछ नहीं है। इसके साथ ही भारत सरकार को चाहिए कि वह ईंधन पर लगाये गये तमाम करों और उपकरों को वापस ले तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में हो रही लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ विश्व जनमत तैयार करने की अवश्य कोशिश करे।

सरकार से यह सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कि पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस लागत मूल्य पर उपलब्ध हो, हम तमाम तबके के लोगों से संयुक्त, संगठित, दीर्घस्थायी और ताकतवर आंदोलन निर्मित करने का आह्वान करते हैं ताकि सरकार को इन जायज मांगों को मानने के लिए मजबूर किया जा सके।''

कानपुर रोहतक और में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता–सहायिकाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन

रोहतक

उत्तर प्रदेश के कानपुर और हरियाणा के रोहतक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका एसोसिएशन (संबद्ध एआईयूटीयूसी) की कानपुर इकाई ने 22 मई को अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला इकाई की अध्यक्ष हीरावती ने किया। उधर हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन (संबंधित एआईयूटीयूसी) की रोहतक इकाई ने 25 मई को रोहतक के मानसरोवर पार्क में इकट्ठा होकर जनसभा की और लघु सचिवालय तक जुलूस निकालकर अपना मांग पत्र सौंपा। यहां जुलूस की अगुवाई एआईयूटीयूसी के प्रदेश सचिव कॉ. हरिप्रकाश, आंगनबाड़ी प्रदेश महासचिव पुष्पा दलाल, जिला प्रधान रोशनी चौधरी, जिला सचिव सुनीता वर्मा आदि ने की।

कानपुर

दिल्ली में मुंडका अग्निकांड पर ट्रेड यूनियनों का संयुक्त प्रदर्शन

रेलवे में भारी संख्या में पदों की समाप्ति का फैसला निजीकरण की ओर बढ़ता कदम -एआईयूटीयूसी

एआईयूटीयूसी के महासचिव कॉमरेड शंकर दासगुप्ता ने 1 जून को निम्नलिखित बयान जारी किया है:

"मीडिया सूत्रों के अनुसार रेलवे के विभिन्न विभागों के 80000 (अस्सी हजार) से अधिक पद समाप्त होने जा रहे हैं। यह भी जानकारी मिली है कि रेलवे की गैर-संरक्षा श्रेणियों की सभी रिक्तियों को तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा। रेलवे बोर्ड की ओर से कई कैटेगरी के पदों को समाप्त करने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है। यहां तक कि विशेष कार्य-अध्ययन के लिए भी कुछ विभाग निर्धारित किये गये हैं, ताकि वहां से अधिक से अधिक पदों को समाप्त किया जा सके। कुल मिलाकर, सम्पूर्ण रेल उद्योग पर गंभीर हमले हो रहे हैं। रेलगाड़ियों, स्टेशनों, यात्रियों, और मालगाड़ियों की संख्या सहित ढोये जाने वाले मालों की मात्रा आदि में कई गुना बढ़ोतरी के बावजूद रेलवे में कभी 22.5 लाख पद थे, जिनकी संख्या घटकर अब लगभग 12 लाख हो गयी है। खबर यह भी है कि लोको पायलट, गार्ड और स्टेशन मास्टर जैसी अत्यंत आवश्यक श्रेणियां में भी कर्मियों की भारी किल्लत है। इससे रेलवे पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, जिसके नतीजतन श्रमिकों पर काम का बोझ बढ़ेगा।

रेलवे के निजीकरण की नीति, जिसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार द्वारा इजारेदार घरानों की सेवा के लिए इसलिए की गयी थी ताकि वे सर्वाधिक मुनाफा लूट सकें, को भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार शासक वर्ग के हित में आक्रामक तरीके से लागू कर रही है।

मोदी सरकार द्वारा उठाया गया गया यह कदम दरअसल रेलवे के पूर्ण निजीकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम है, जो रोजगार के अवसर घटाकर, रेलकर्मियों के काम के बोझ बढाकर, रेलवे द्वारा वहन किये जाने वाले सभी सामाजिक दायित्वों को खत्म कर रेल किराये में बढ़ोतरी तथा आवश्यक वस्तुओं के दाम में इजाफा करते हुए रेल कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों के जीवन और आजीविका पर गंभीर प्रभाव डालेगा। इसका सम्पूर्ण उद्देश्य बड़े इजारेदार घरानों के मुनाफे को और अधिक बढ़ाना है।

इस पृष्ठभूमि में एआईयूटीयूसी, खास तौर पर रेलवे यूनियनों और मजदूरों से अपनी संबद्धता का लिहाज किये बगैर और आम तौर पर जन सामान्य से आग्रह करती है कि वे भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के इस जघन्य मंसूबे के खिलाफ ताकतवर जन आंदोलन का निर्माण करें।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."
Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631, 9868350503